

नवसर्जन संस्कृति

RNI No.: UPHIN/25/A1698
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 347
दि. 20.04.2026,
सोमवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

विपक्ष के रवैये की तुलना यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने द्रौपदी के 'चौरहण' से की, बिनाए पुराने आरोप

(एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कठकअ गठबंधन ने महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में एक तिहाई आरक्षण देने वाले ऐतिहासिक संविधान संशोधन विधेयक को जानबूझकर हराने की कोशिश की। उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के व्यवहार की तुलना महाभारत की द्रौपदी के चौरहण से करते हुए कहा कि यह घटना महिलाओं के प्रति विपक्ष की 'असलियत' उजागर कर देती है।

विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब देश महिलाओं को राजनीतिक सत्ता में उचित हिस्सा देने जा रहा था, तब विपक्ष ने एक बार फिर पुरानी आदत के मुताबिक बाधा डाली। शुकवार 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में तीन महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए गए थे: संविधान (131वां संशोधन) विधेयक परिसीमन विधेयक 2026 केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 इनका उद्देश्य था- लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 816 करना 2011 की जनगणना के आधार पर नए सिरे से परिसीमन करना 2029 के चुनाव से लोकसभा और सभी विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देना

सरकार का तर्क था कि सीटें बढ़ाने से कोई मौजूदा सांसद या विधायक अपनी सीट नहीं खोएगा और महिलाओं को बिना किसी को विस्थापित किए प्रतिनिधित्व मिल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिणी राज्यों को आश्वासन भी दिया था कि उनका प्रतिनिधित्व भी उसी अनुपात में बढ़ेगा। लेकिन मतदान के समय विधेयक दो-तिहाई बहुमत हासिल नहीं कर सका। 298 सदस्यों ने पक्ष में वोट दिया, जबकि 230 ने विरोध में। दो-तिहाई बहुमत के लिए करीब 352 वोट जरूरी थे। विधेयक गिर गया और सरकार को इसे वापस लेना पड़ा। यह मोदी सरकार के कार्यकाल में पहला ऐसा मौका था जब कोई महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक सदन में पास नहीं हो सका।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 'जब सदन में जो दृश्य देखने को मिला, वह हमें मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि 2014 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा था कि देश में का विरोध किया। विपक्ष पर पुराने आरोप दोहराए योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर कई पुराने मुद्दे भी उठाए- शाह बानो मामले में कांग्रेस ने मुस्लिम महिलाओं को न्याय से वंचित रखा। तीन तलाक पर प्रतिबंध लगाने का काम मोदी सरकार ने किया। सपा और आरजेडी ने 1990 के दशक से ही महिला आरक्षण का विरोध किया। 1998 में आरजेडी सांसद ने सदन में विधेयक फाड़ दिया था। जब 2010 में राज्यसभा ने विधेयक पास किया, तब भी कांग्रेस ने लोकसभा में इसे कभी पेश नहीं किया, भले ही बहुमत था। अब सपा मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग आरक्षण की मांग कर रही है, जबकि संविधान सभा ने धर्म आधारित आरक्षण को सिरे से खारिज कर दिया था। बाबासाहेब अंबेडकर

सिर्फ चार जातियां हैं, महिलाएं, गरीब, युवा और किसान। उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग जाति की राजनीति के नाम पर देश को लूटते रहे, उन्होंने इस घोषणा को चुनौती मान लिया और हर प्रगतिशील कदम का विरोध किया। विपक्ष पर पुराने आरोप दोहराए योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर कई पुराने मुद्दे भी उठाए- शाह बानो मामले में कांग्रेस ने मुस्लिम महिलाओं को न्याय से वंचित रखा। तीन तलाक पर प्रतिबंध लगाने का काम मोदी सरकार ने किया। सपा और आरजेडी ने 1990 के दशक से ही महिला आरक्षण का विरोध किया। 1998 में आरजेडी सांसद ने सदन में विधेयक फाड़ दिया था। जब 2010 में राज्यसभा ने विधेयक पास किया, तब भी कांग्रेस ने लोकसभा में इसे कभी पेश नहीं किया, भले ही बहुमत था। अब सपा मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग आरक्षण की मांग कर रही है, जबकि संविधान सभा ने धर्म आधारित आरक्षण को सिरे से खारिज कर दिया था। बाबासाहेब अंबेडकर

और सरदार पटेल ने इसका कड़ा विरोध किया था। मुख्यमंत्री ने पूछा, 'क्या यह विधेयक पुरुषों के अधिकारों का हनन करता है? नहीं। यह तो महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रगतिशील कदम है।' महिलाओं में भारी गुस्सा योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि देश की 'आधी आवादी' में विपक्ष के इस रवैये को लेकर भारी गुस्सा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और कठकअ गठबंधन के सहयोगी दलों (सपा, फख्रुल ज़त, ज़त) ने इस 'पाप' में हिस्सा लिया है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहीं और उन्होंने महिला आरक्षण को राष्ट्रीय हित का मुद्दा बताया। राजनीतिक इच्छाशक्ति को कमी 17 अप्रैल 2026 की घटना महिला आरक्षण के 30 साल पुराने

इतिहास को दोहराती है। 1996 से लेकर अब तक हर सरकार में यह विधेयक किसी न किसी बहाने अटका रहा। कभी ओबीसी कोटा, कभी परिसीमन, कभी क्षेत्रीय असंतुलन का मुद्दा उठाया गया। जबकि जमीनी स्तर पर पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण मिला हुआ है और वे सफलतापूर्वक नेतृत्व कर रही हैं, संसद-विधानसभा जैसे उच्च स्तर पर सत्ता साझा करने में राजनीतिक दल अभी भी हिचकिचा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की द्रौपदी चौरहण वाली टिप्पणी विवादास्पद जरूर है, लेकिन एक बड़े सवाल को फिर से उठा दिया है कि क्या महिलाओं को राजनीतिक सत्ता में उनका हक देने के लिए देश को अभी भी और इंजाम करना पड़ेगा? देश की महिलाएं अब इस सवाल का जवाब खुद तय करने वाली हैं।

टीसीएस के बाद अब डी-मार्ट में धर्मांतरण का खेल? सोहेल पर लगा सहकर्मी का धर्म बदलवाने का आरोप

(एजेंसी)। महाराष्ट्र में धर्मांतरण को लेकर छिड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। नासिक स्थित टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) में सामने आए कथित उन्नीडन और धर्मांतरण के मामले की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि अब शिर्डी के डी-मार्ट (D-Mart) स्टोर में भी इसी तरह के गंभीर आरोप सामने आए हैं। आरोप है कि स्टोर के ही एक कर्मचारी ने अपने सहकर्मी का 'ब्रेनवॉश' कर उसका धर्म परिवर्तन कराया है, जिसके बाद शिर्डी में तनाव की स्थिति बनी हुई है। आइए जानते हैं नासिक टीसीएस से लेकर शिर्डी डी-मार्ट तक धर्मांतरण के इन आरोपों के पीछे का पूरा घटनाक्रम क्या है। शिर्डी डी-मार्ट मामले: अश्विन से 'मुस्तफा' बनने का दावा शिर्डी स्थित डी-मार्ट स्टोर में काम करने वाले एक युवक अश्विन के धर्म परिवर्तन को लेकर हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, आरोप है कि स्टोर के ही एक अन्य

कर्मचारी सोहेल मनियार ने अश्विन को धर्म बदलने के लिए उकसाया और उसका मानसिक रूप से 'ब्रेनवॉश' किया। विवाद नासिक के TCS कार्यालय को लेकर है, जहां महिला कर्मचारियों के साथ कथित उत्पीड़न और धर्मांतरण के प्रयासों के आरोप लगे हैं। SAT जांच: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच दल (SAT) का गठन किया है। फेक्ट फाइंडिंग कमेटी: राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) द्वारा गठित चार सदस्यीय कमेटी (जिसमें एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी और एडवोकेट मोनिका अरोड़ा शामिल हैं) ने 18-19 अप्रैल को पीड़ितों से मुलाकात की। जांच का स्टेटस: एडवोकेट मोनिका अरोड़ा ने कहा, 'मामला बेहद संवेदनशील और खुलासा करने वाली प्रकृति का है। हम सभी पक्षों से बात करने के बाद अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपेंगे।' महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस मुद्दे पर हाई-लेवल बैठक की। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि, 'धर्मांतरण से जुड़े मामलों को किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।'

दावा: सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि अश्विन ने अपना नाम बदलकर 'मुस्तफा' रख लिया है और अपने प्रोफाइल में भी बदलाव किए हैं। विरोध: खबर फैलते ही हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, आरोप है कि स्टोर के ही एक अन्य

अब 'चिप हब' बनेगी दिल्ली? नौकरी से निवेश तक, सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा प्लान

दिल्ली की अर्थव्यवस्था और तकनीकी भविष्य को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली सरकार ने अपनी बहुप्रतीक्षित 'दिल्ली सेमीकंडक्टर पॉलिसी' का ड्राफ्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में लिया गया यह फैसला दिल्ली को न केवल भारत, बल्कि दुनिया के नक्शे पर सेमीकंडक्टर डिजाइन, रिसर्च और डेवलपमेंट (फैक्ट्री) के एक बड़े केंद्र के रूप में स्थापित करने वाला है। सीएम का मानना है कि यह नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' के सपने को साकार करने में दिल्ली की भागीदारी को सबसे मजबूत बनाएगी। दिल्ली बनेगी 'टेक हब': पॉलिसी के पीछे क्या है विजन? मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के अनुसार, सेमीकंडक्टर आज के दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुके हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार एक ऐसा ढांचा तैयार कर रही है जो इस क्षेत्र के संतुलित और व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करे।

पीएम मोदी ने तृणमूल कांग्रेस के 'सिंडिकेट' और अपराधियों को दो-टूक शब्दों में आखिरी चेतावनी दी

(एजेंसी)। पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक का सबसे बड़ा और तीखा हमला बोला है। बांकुरा की पावन धरती से हुंकार भरते हुए पीएम मोदी ने तृणमूल कांग्रेस के 'सिंडिकेट' और अपराधियों को दो-टूक शब्दों में आखिरी चेतावनी दे डाली है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मंच से गरजते हुए कहा कि 29 अप्रैल तक का समय है, जिसे भी अपनी सलामती चाहिए वो थाने में जाकर सरेंडर कर दे, क्योंकि 4 मई के बाद 'महासंग्राम' शुरू होगा और किसी भी गुनहवार को बख्शा नहीं जाएगा। यह सिर्फ एक चुनावी रैली नहीं थी, बल्कि बंगाल के कथित 'महा जंगलराज' के खिलाफ मोदी का खुला ऐलान था। बांकुरा की जनसभा में पीएम मोदी का तेवर देख लोग हैरान रह गए। उन्होंने विष्णुपुर के माफिया और टीएमसी के सिंडिकेट को सीधी चेतावनी दी। उन्होंने कहा, 'मैं टीएमसी के सभी गुंडों, सिंडिकेट चलाने वालों और भ्रष्टाचारियों को आखिरी मौका दे रहा हूँ। 29 अप्रैल से पहले अपने करीबी पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दो। याद रखना, 4 मई के बाद कोई बच नहीं पाएगा।' पीएम का यह अल्टीमेटम बंगाल में कानून-व्यवस्था और भ्रष्टाचार को चुनौती दे रहा है। उन्होंने कहा कि 20 लाख तक का ऋण मिलेगा।

साफ कर दिया बंगाल में अब अपराधियों की मनमानी नहीं चलेगी। बंगाल की बेटियों को मोदी की 'गारंटी': सालाना 36,000 और फ्री इलाज पधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि टीएमसी ने बंगाल की बहनों के साथ गहरी की है। उन्होंने बंगाल में बीजेपी सरकार पर महिलाओं के लिए 'सौगातों का पिटारा' खोल दिया। पीएम मोदी ने वादा किया कि: सालाना आर्थिक मदद: बंगाल की हर बहन को हर साल ₹36,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुफ्त इलाज: आयुष्मान योजना के तहत ₹5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिर्सा और किडनी के मरीजों के लिए सरकारी अस्पतालों में मुफ्त डायलिसिस की सुविधा होगी। मातृत्व लाभ: गर्भवती महिलाओं को ₹21,000 और बच्चे के जन्म के बाद पढ़ाई के लिए ₹5,000 अतिरिक्त दिए जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत: मुद्रा योजना के तहत स्वरोजगार के लिए महिलाओं को ₹20 लाख तक का ऋण मिलेगा।

बेटी की पढ़ाई: बेटियों की शिक्षा के लिए ₹50,000 की सहायता राशि का प्रावधान किया जाएगा। आदिवासी राष्ट्रपति का अपमान 'घुसपैटियों' का प्रेम 'ममता नहीं चाहती कि बेटियां सांसद बनें' - आरक्षण पर बड़ा खुलासा प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में हाल ही में हुए महिला आरक्षण बिल (33%) के घटनाक्रम को लेकर भी ममता बनर्जी को घेरा। उन्होंने कहा कि बंगाल की महिलाएं चाहती थीं कि यह आरक्षण 2029 से लागू हो और उन्हें ज्यादा मौका मिले, लेकिन टीएमसी और कांग्रेस ने मिलकर साजिश रची ताकि बंगाल की बेटियां लोकसभा और विधानसभा न पहुंच सकें। मोदी के मुताबिक, टीएमसी को डर है कि अगर पढ़ी-लिखी बेटियां राजनीति में आईं, तो उनके सिंडिकेट राज को चुनौती देंगी। इसलिए उन्होंने इस कानून को रोकने की भरपूर कोशिश की। 4 मई के बाद बंगाल में 'डबल इंजन' का धमका? पीएम मोदी के इस भाषण ने बंगाल चुनाव के आखिरी चरणों में गर्मी बढ़ा दी है। एक तरफ जहां उन्होंने सीधे तौर पर अपराधियों को डराया है, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के लिए बड़ी योजनाओं का ऐलान कर ममता बनर्जी के 'महिला वोट बैंक' में संघ लगाने की कोशिश की है। पीएम ने कहा कि बंगाल की जनता अब इस 'महा जंगलराज' को बर्दाश्त नहीं करेगी और आगामी चुनाव में टीएमसी को कड़ी से कड़ी सजा देगी।

गौतम अडानी ने तारंगा मंदिर में मांगी सुख-समृद्धि

अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने रविवार को अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर गुजरात की तारंगा पहाड़ियों पर स्थित ऐतिहासिक श्री अजीतनाथ भगवान श्वेतांबर जैन देरासर के दर्शन किए। इस दौरान उनकी पत्नी डॉ. प्रीति अडानी भी उनके साथ मौजूद रहीं। यह मंदिर क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। अडानी दंपति सुबह मेहसाणा जिले के खेरालू तालुका स्थित दाभोड़ा हेलीपैड पहुंचे। वहां जैन समुदाय के लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, जिसके बाद वे पहाड़ी पर स्थित मंदिर के लिए रवाना हुए। अक्षय तृतीया को हिंदू और जैन दोनों ही परंपराओं में बेहद शुभ माना जाता है।

सौर ऊर्जा में लखनऊ बना नंबर-1! देशभर में रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में टॉप पर पहुंचा शहर

(जीएनएस)। लखनऊ ने पीएम सूर्य घर योजना के तहत 87,000 से अधिक रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित कर देश में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जिससे यह सौर ऊर्जा में अग्रणी जिला बना। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए देशभर में सोलर इंस्टॉलेशन के मामले में शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य में चल रहे रूफटॉप सौर ऊर्जा के क्षेत्र में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत अभियान ने लखनऊ को राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बना दिया है। उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा अधिकरण के निदेशक इंद्रजीत

सिंह ने बताया कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत लखनऊ में अब तक 87,000 से अधिक रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जो देश के किसी भी जिले में सबसे अधिक हैं। 15 अप्रैल तक लखनऊ में 3,133 रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए गए। यह उपलब्धि लखनऊ को सोलर ऊर्जा अपनाने के मामले में देश का अग्रणी जिला बनाती है। सौर ऊर्जा अपनाने में बढ़ती जागरूकता और मांग विशेषज्ञों के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में घरेलू गैस के स्थान पर इंडक्शन कुकटॉप के बढ़ते उपयोग तथा इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग के कारण बिजली की खपत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके साथ ही, बढ़ते बिजली बिल को नियंत्रित करने की इच्छा और पर्यावरण संरक्षण के प्रति बढ़ती जागरूकता ने लोगों को तेजी से सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रेरित किया है। रूफटॉप सोलर सिस्टम उपभोक्ताओं को दीर्घकालिक आर्थिक लाभ प्रदान कर रहे हैं और उन्हें ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना रहे हैं। सरकारी योजनाओं और सब्सिडी

12 कोच वाली नान एसी ट्रेन का ट्रायल शुरू, यात्रियों को क्या मिलेगी सुविधाएं? मुंबई में लोकल ट्रेन में चलने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। लाखों यात्रियों के लिए दैनिक यात्रा को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से शहर में जल्द ही बंद दरवाजे वाली गैर-एसी लोकल ट्रेन शुरू हो रही हैं। ट्रेन के चलते समय दरवाजे बंद रहने से दुर्घटनाओं का खतरा काफी हद तक कम हो सकता है, जिसकी मुंबई को वर्षों से जरूरत है। सेंट्रल रेलवे ने अपनी पहली 12-कोच वाली नॉन-एसी लोकल ट्रेन का ट्रायल शुरू कर दिया है। यह अत्याधुनिक एटव रैक की सबसे प्रमुख विशेषता है कि इसमें ऑटोमैटिक डोर लगे हैं जो एंटी-ड्रैग सुविधा से युक्त हैं।

आईएसएस स्पेस स्टेशन में लोकनृत्य बिहू का दिखा जलवा, असम चुनाव के बीच वीडियो वायरल, कौन हैं ये अंतरिक्ष यात्री?

(जीएनएस)। असम का पारंपरिक बिहू नृत्य अब धरती की सीमाएं पार कर अंतरिक्ष तक पहुंच गया है। अंतरिक्ष में बिहू नृत्य का अनोखा दृश्य वायरल हो रहा है, जिसमें अंतराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (ISS) पर एक अंतरिक्ष यात्री असम के पारंपरिक बिहू पर नाचते नजर आ रहे हैं। दरअसल, ये वीडियो असम के मुख्यमंत्री हिमंत सरमा ने शेयर किया है, जिसमें ISS पर मौजूद अंतरिक्ष यात्री बिहू की धुन पर थिरकते नजर आ रहे हैं। सीएम ने जताई खुशी, पीएम मोदी को दिया श्रेय वीडियो शेयर करते हुए सरमा ने इस पल को असम के लिए गर्व का क्षण बताया। उन्होंने अंतरिक्ष यात्री

माइक फिंके की सराहना की और प्रधानमंत्री का भी धन्यवाद किया। उनके मुताबिक, #BihuBinandia जैसे आयोजनों के चलते बिहू को वैश्विक पहचान मिली है। 'बिहू बिनांदिया' से मिली थी बड़ी पहचान

बाता दें कि 'बिहू बिनांदिया' अप्रैल 2023 में गुवाहाटी में आयोजित एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम था, जिसमें करीब 10,000 कलाकारों ने हिस्सा लिया था। इस ऐतिहासिक आयोजन में

प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहे थे, जिससे इस लोकनृत्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। वीडियो फिर हुआ वायरल 'द असम ट्रिब्यून' के अनुसार, माइक फिंके का यह वीडियो नया नहीं है, बल्कि हाल ही में फिर से सोशल मीडिया पर सामने आया है। यह ऐसे समय में वायरल हो रहा है, जब अरंभ में रंगाली बिहू और असमिया नववर्ष का जश्न मनाया जा रहा है। वीडियो में फिंके गले में असमिया गमछा डालकर बिहू करते दिखते हैं। दिलचस्प बात यह है कि माइक फिंके की पत्नी रेनिता सैकिया असम की रहने वाली हैं और NASA में कार्यरत हैं। यही नहीं, फिंके अमेरिकी वायु सेना के रिटायर्ड कर्नल हैं और 1996 में उन्हें अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया था।

JioTV
CHENNAL NO. 2063

Jio FIBER

Jio tv+

Daily Hunt

ebaba TV

Dish Plus

DTH live OTT

Rock TV

Airtel

Amezone Fire

Roku Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार प्राप्त करने के लिए आज ही नवसर्जन संस्कृति हिंदी चैनल देखिये

उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर पर ब्रेक! उपभोक्ताओं को राहत, सरकार पर अखिलेश यादव ने कसा 'हेराफेरी' का तंज

(एजेंसी)। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटरों के खिलाफ बढ़ रहे जन-आक्रोश और तकनीकी खामियों की शिकायतों को देखते हुए योगी सरकार ने बेहद सख्त कदम उठाया है। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने प्रदेश में पुराने मीटरों को स्मार्ट मीटर में बदलने की प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इसके साथ ही बिजली और कनेक्शन काटने को लेकर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने वाले कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने शक्ति भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री के निर्देशन में गठित तकनीकी समिति जब तक अपनी रिपोर्ट नहीं देती, तब तक पुराने मीटरों को स्मार्ट मीटर में बदलने का काम बंद रहेगा।

कनेक्शन काटने पर 45 दिन की राहत

उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए मंत्री ने निर्देश दिया कि जहां हाल ही में स्मार्ट मीटर लगे हैं, वहां अगले 45 दिनों तक (15 दिन कनेक्शन + 30 दिन अतिरिक्त) किसी भी उपभोक्ता का कनेक्शन बिजली बिल बकाया होने पर नहीं काटा जाएगा।

जिरो बैलेंस पर भी नहीं कटेगी बिजली

2 किलोवाट तक के भार वाले उपभोक्ताओं के लिए विशेष व्यवस्था



की गई है। यदि उनका बैलेंस जीरो हो जाता है, तब भी अधिकतम 3 दिन या ₹200 तक की नेगेटिव लिमिट तक बिजली आपूर्ति बाधित नहीं होगी।

5-स्तरीय रटर अलर्ट प्रणाली: उपभोक्ताओं को बिल और बैलेंस की सटीक जानकारी देने के लिए अब 5 चरणों में मैसेज भेजे जाएंगे:

पहला: बैलेंस 30% बचने पर।
दूसरा: बैलेंस 10% बचने पर।
तीसरा: बैलेंस पूरी तरह समाप्त होने पर

चौथा: बिजली काटने से एक

दिन पहले।

पांचवां: कनेक्शन डिस्कनेक्ट होने के बाद।

छठी के दिन नो डिस्कनेक्शन:

मंत्रि ने सख्त निर्देश दिए कि रविवार या किसी भी सरकारी अवकाश के दिन, बैलेंस नेगेटिव होने पर भी किसी भी स्थिति में बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा।

सरकार को आखिर क्यों लेना पड़ा यह फैसला?

दरअसल, स्मार्ट मीटरों को लेकर पूरे प्रदेश में विरोध की लहर चल रही है। हाल ही में राज्य के अलग-अलग इलाकों से भारी हंगामे की खबर सामने आई है, जहां महिलाओं और पुरुषों ने सड़क जाम कर विद्युत

विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शिकायतें: उपभोक्ताओं का आरोप है कि बिल जमा होने के बावजूद महीने में कई बार बिजली काट दी जाती है।

अविध बिलिंग: लोगों का कहना है कि मीटर बहुत तेज भाग रहे हैं और पुराने मीटरों की तुलना में 4 से 5 हजार रुपये तक के फर्जी बिल आ रहे हैं।

सियासी बार-पलटवार: अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा

स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे भाजपा का 'भ्रष्टाचार' करार दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया () पर तीखा हमला करते हुए लिखा कि, 'स्मार्ट मीटर के नाम पर चल रही ठगी के खिलाफ जनता का गुस्सा का मीटर हाई है। भाजपा के बिजली मीटर भी एश्ट मशीन की तरह हेराफेरी करते हैं। भाजपा ने मीटर कंपनियों से एडवांस कमीशन ले लिया है, जिसकी वसूली जनता से तेज दौड़ने वाले मीटर लगाकर की जा रही है।' अखिलेश ने चेतावनी देते हुए कहा कि महंगाई और बिजली के बढ़ते बिल ही भाजपा का सत्ता से कनेक्शन काट देंगे।

किम जोंग उन ने पूर्वी सिनपो क्षेत्र से समुद्र की ओर कई कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, डर से कांप उठे जापान और अमेरिका!

(एजेंसी)। उत्तर कोरिया द्वारा हाल ही में किए गए मिसाइल परीक्षणों ने एशियाई क्षेत्र में हलचल मचा दी है। रविवार सुबह पूर्वी सिनपो क्षेत्र से समुद्र की ओर कई कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं। इस साल अब तक सात बार और अकेले अप्रैल महीने में चार बार ऐसे परीक्षण हो चुके हैं।

इन गतिविधियों से दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका की चिंताएं बढ़ गई हैं। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन अपनी सेना को आधुनिक बनाने और परमाणु हथियारों की ताकत बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं, जिससे पड़ोसी देशों के बीच तनाव चरम पर है।

पड़ोसी देशों में बढ़ी बेचैनी

उत्तर कोरिया की इन हरकतों से दक्षिण कोरिया और जापान पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आपातकालीन टीम बुलाई है। दक्षिण कोरिया और

अमेरिका के साथ मिलकर मिसाइलों के डेटा का विश्लेषण किया जा रहा है। जापान ने उत्तर कोरिया के सामने कड़ा फैला देता है, जिससे पूरा शहर अंधेरे में डूब सकता है और बिजली गिड़ तबाह हो जाते हैं। इसके अलावा उत्तर कोरिया ने क्लस्टर बम और हवा से मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों



खोफ

हालिया परीक्षणों में सबसे ज्यादा चर्चा 'कार्बन-फाइबर बम' की हो रही है, जिसे 'ब्लैकआउट बम' भी कहा

जाता है। यह हथियार सीधा धमका करने के बजाय पावर प्लांट और बिजली सप्लाई लाइनों पर बारीक रेशे फेंका देता है, जिससे पूरा शहर अंधेरे में डूब सकता है और बिजली गिड़ तबाह हो जाते हैं। इसके अलावा उत्तर कोरिया ने क्लस्टर बम और हवा से मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों

इन् परीक्षणों ने कोरियाई प्रायद्वीप में शांति की संभावनाओं को कम कर दिया है। दक्षिण कोरिया के लिए यह स्थिति सबसे अधिक चिंताजनक है क्योंकि उसकी सीमाएं उत्तर कोरिया से जुड़ी हैं। अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया अब अपनी रणनीति बदल रहे हैं ताकि किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। क्षेत्र में हथियारों की यह होड़ आने वाले समय में एक बड़े सुरक्षा संकट का रूप ले सकती है।

जापान के भी सफल टेस्ट किया है। सेना को आधुनिक बना रहे किम किम जोंग उन खुद इन परीक्षणों की निगरानी कर रहे हैं। उनका मुख्य

मकसद उत्तर कोरिया के मिसाइल भंडार को और भी घातक और आधुनिक बनाना है। वे ऐसी परमाणु मिसाइलें तैयार करना चाहते हैं जो दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को आसानी से चकमा दे सकें। विशेषज्ञों का मानना है कि किम जोंग अपनी सैन्य शक्ति दिखाकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाना चाहते हैं और अपनी सुरक्षा को और पुख्ता करना चाहते हैं।

बढ़ता क्षेत्रीय तनाव और खतरा

इन् परीक्षणों ने कोरियाई प्रायद्वीप में शांति की संभावनाओं को कम कर दिया है। दक्षिण कोरिया के लिए यह स्थिति सबसे अधिक चिंताजनक है क्योंकि उसकी सीमाएं उत्तर कोरिया से जुड़ी हैं। अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया अब अपनी रणनीति बदल रहे हैं ताकि किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। क्षेत्र में हथियारों की यह होड़ आने वाले समय में एक बड़े सुरक्षा संकट का रूप ले सकती है।

तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में पटाखा फैक्ट्री में कैसे हुआ ब्लास्ट? जिसमें झुलसी 23 जिंदगियां

(एजेंसी)। तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में एक पटाखा फैक्ट्री विस्फोट में 16 मजदूरों की मौत हो गई है। छह अन्य गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। रविवार को कट्टनारपट्टी की वनजा पटाखा फैक्ट्री में यह दुर्घटना हुई, जिस दौरान श्रमिक काम कर रहे थे। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है।

पहले चार मौतों की खबर थी, जो अब तक बढ़कर 23 तक पहुंच गई है। विस्फोट इतना भीषण था कि फैक्ट्री की चार इमारतें पूरी तरह ढह गईं। धमाके का कंपन लगभग 10 किलोमीटर के दायरे तक महसूस किया गया। सूचना मिलते ही अग्निशमन दल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा।

अग्निशमनकर्मियों ने आग पर काबू पाया और घायलों को मलबे से निकालकर नजदीकी अस्पतालों में पहुंचाया। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। मौके पर बचाव कार्य अभी भी जारी है, जिसमें मलबे से और लोगों के मिलने की संभावना है।

कैसे हुआ पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट?

तमिलनाडु की इस फैक्ट्री में ब्लास्ट का सटीक कारण अभी आधिकारिक रूप से स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार गोविंदनल्लूर निवासी मुथु माणिकम की पटाखा फैक्ट्री में यह घटना तब हुई जब मजदूर 'फैसी' पटाखों की लड़ियां जोड़ने का काम कर रहे थे। दुर्घटना संभवतः पटाखे



बनाने में इस्तेमाल होने वाले ज्वलनशील रसायनों के घर्षण, अधिक गर्मी और सुरक्षा नियमों में लापरवाही के कारण हुई हो सकती है।

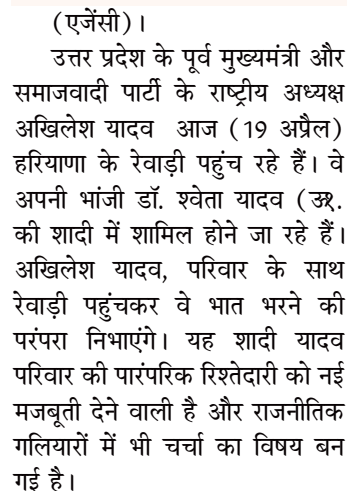
में आतिशबाजी उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है, जहां हजारों फैक्ट्रियां चलती हैं। इस क्षेत्र, खासकर Sivakasi, में पहले भी ऐसे हादसे होते रहे हैं। 13 अप्रैल को पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था। यहाँ केमिकल्स की गलत हैंडलिंग या सुरक्षा मानकों की कमी से विस्फोट हो जाते हैं, इसलिए इस मामले में भी जांच के बाद ही अंतिम कारण स्पष्ट होगा। इस क्षेत्र में बार-बार होने वाले ऐसे विस्फोट पटाखा उद्योग में सुरक्षा मानकों के उचित पालन की कमी पर गंभीर सवाल उठाते हैं।

आतिशबाजी फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों का क्या नहीं हो रहा पालन? विरुधुनगर जिला, विशेषकर शिवकाशी और सात्तूर क्षेत्र, तमिलनाडु

अखिलेश यादव की भांजी डॉ. श्वेता यादव कौन हैं, जिसकी शादी में सपाइयों का मेला?

(एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज (19 अप्रैल) हरियाणा के रेवाड़ी पहुंच रहे हैं। वे अपनी भांजी डॉ. श्वेता यादव (उ.प्र.) की शादी में शामिल होने जा रहे हैं। अखिलेश यादव, परिवार के साथ रेवाड़ी पहुंचकर वे भात भरने की परंपरा निभाएंगे। यह शादी यादव परिवार की पारंपरिक रिश्तेदारी को नई मजबूती देने वाली है और राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बन गई है।

रेवाड़ी के ओल्ड राव पैलेस में आज डॉ. श्वेता यादव और डॉ. ऋषभ यादव का विवाह हो रहा है। यह एक अरेंज मैरिज है, जिसमें दोनों परिवार लंबे समय से एक-दूसरे को जानते-पहचानते हैं। शादी के मौके पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और



सा लगने वाला है। बाएं तरफ अखिलेश यादव का भांजा-भांजी, बीच में चुआ। दाएं तरफ अखिलेश यादव के साथ भांजा। डॉ. श्वेता यादव रेवाड़ी के बूढ़पुर गांव निवासी सुखबीर सिंह यादव की बेटी हैं। उनकी स्कूलिंग रेवाड़ी में हुई

नेता भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, जिससे रेवाड़ी में सपाइयों का मेला- और उन्होंने गाजियाबाद से MBBS पढ़ाई पूरी की। वे विराट अस्पताल में डॉक्टर के रूप में काम करती हैं। श्वेता के भाई डॉ. विराटवीर बाल रोग विशेषज्ञ हैं और 2017 से रेवाड़ी में विराट अस्पताल चला रहे हैं। श्वेता यादव परिवार की तीसरी पीढ़ी का हिस्सा हैं, जो चिकित्सा क्षेत्र में सक्रिय हैं। उनके नाना-नानी की पीढ़ी से

यादव परिवार की जड़ें हरियाणा से जुड़ी हुई हैं। डॉ. श्वेता का दूल्हा डॉ. ऋषभ यादव रेवाड़ी के झाल गांव निवासी राजबीर यादव के बड़े बेटे हैं। राजबीर यादव कृष्णा एजुकेशन सोसाइटी के नाम से स्कूल और कॉलेज चलाते हैं। ऋषभ की स्कूलिंग कोसली में हुई। उन्होंने बरेली से टैडर पूरा किया और फिलहाल मास्टर ऑफ चिरुर्जिया की पढ़ाई कर रहे हैं। दोनों परिवार लंबे समय से एक-दूसरे को जानते हैं। श्वेता की मेडिकल पढ़ाई पूरी होने के बाद दोनों परिवारों ने रिश्ते पर विचार किया। जब श्वेता और ऋषभ से पूछा गया, तो दोनों ने सहमति जताई। इस तरह पुरानी जान-पहचान अब रिश्तेदारी में बदल रही है। यादव परिवार की हरियाणा से गहरी रिश्तेदारी

नेहरू सेंटर, लंदन में 'संवेदनाओं का सफर' में साहित्य और संवेदनाओं से सजी यादगार संध्या



अपने साहित्यिक और सामाजिक योगदान के लिए लंदन में प्राप्त प्रतिष्ठित पुरस्कार के साथ लोढ़ा फाउंडेशन की अध्यक्षा डॉ. मंजू मंगलप्रभात लोढ़ा। अन्य चित्र में नेहरू सेंटर, लंदन में आयोजित साहित्यिक काव्य सत्र "संवेदनाओं का सफर" में विभिन्न गणमान्य अतिथि डॉ. मंजू लोढ़ा की नई पुस्तकों के साथ तथा अंतिम चित्र में सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री तेजेन्द्र शर्मा के साथ डॉ. मंजू लोढ़ा के संवाद सत्र का दृश्य।

साहित्यिक और सामाजिक योगदान के लिए डॉ. मंजू लोढ़ा को लंदन में प्रतिष्ठित पुरस्कार

मुंबई, 18 अप्रैल। लंदन स्थित नेहरू सेंटर में आयोजित 'संवेदनाओं का सफर' शीर्षक से साहित्यिक वार्ता एवं काव्य सत्र एक अविस्मरणीय और भावपूर्ण संध्या के रूप में सम्पन्न हुआ। इस कार्यक्रम में साहित्य, संवाद और संवेदनाओं का अद्भुत संगम देखने को मिला, जिसने उपस्थित सभी दर्शकों के हृदय को स्पर्श किया।

इस गरिमापूर्ण आयोजन में श्री वीरेन्द्र शर्मा, लॉर्ड उदय नगराज, डॉ. अनुराधा पांडेय, श्री कुलदीप

शेखावत, मेयर प्रेरणा, रितु हिंदुजा जैसे अनेक प्रतिष्ठित अतिथियों की उपस्थिति रही। सभी गणमान्य अतिथियों ने लोढ़ा फाउंडेशन की अध्यक्षा तथा सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉ. मंजू मंगलप्रभात लोढ़ा के साहित्यिक योगदान और उनकी पुस्तकों पर अपने हृदयस्पर्शी विचार व्यक्त किये, जो उनके लिए अत्यंत भावुक और यादगार क्षण बन गये। समारोह का मुख्य आकर्षण सुप्रसिद्ध साहित्यकार तेजेन्द्र शर्मा के साथ डॉ. मंजू लोढ़ा का संवाद रहा, जिसमें उन्होंने अपनी साहित्यिक यात्रा, जीवन के अनुभवों और अपनी लेखनी के पीछे की भावनाओं को साझा किया। इस अवसर पर उन्होंने अपनी दो नई

पुस्तकों का प्रीव्यू भी प्रस्तुत किया, जिन्हें दर्शकों से विशेष सराहना मिली। इंदु बरोट ने डॉ. मंजू लोढ़ा की पुस्तकों और काव्य पर अत्यंत सुंदर, गहन और सरस्वती वंदना सट्टा भावों से परिपूर्ण अपने विचार प्रस्तुत किए, जिसने कार्यक्रम की गरिमा को और भी ऊँचाई दी। कार्यक्रम की शुरुआत धृति बाफना द्वारा प्रस्तुत सरस्वती वंदना से हुई, जिसने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। वहीं डॉ. अनिता नायर के प्रभावशाली और सुसंगठित संचालन ने पूरे आयोजन को सहज, गरिमामय और प्रवाहपूर्ण बनाए रखा। यह साहित्यिक संध्या प्रेम, प्रोत्साहन और शब्दों की शक्ति का एक सुंदर उत्सव रही, जिसने सभी

को एक सूत्र में बांधते हुए हिंदी साहित्य को वैश्विक मंच पर नई ऊँचाई प्रदान की। अगले दिन आयोजित एक अन्य गरिमामय समारोह में डॉ. मंजू मंगलप्रभात लोढ़ा को उनके साहित्यिक योगदान एवं समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार 'IIV She Inspires Awards 2026' से सम्मानित किया गया। यह प्रतिष्ठित सम्मान उनके निरंतर समर्पण, साहित्य सेवा और महिला सशक्तिकरण के प्रति उनके उल्लेखनीय योगदान का प्रतीक है, जिसने अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का गौरव और अधिक बढ़ाया इस सम्मान समारोह का आयोजन रश्मि द्वारा किया गया।

'बेअदबी रोकने का स्थायी समाधान,' सत्कार बिल पास होते ही 'आप' के मंत्री चीमा ने विपक्ष को घेरा

(एजेंसी)। पंजाब की राजनीति में धर्म और कानून के बीच संतुलन को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है। भगवंत मान सरकार द्वारा 'जागत ज्योति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक-2026' को मंजूरी मिलने के बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। इसी बीच राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए इस बिल को स्थायी समाधान बताया।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बिल पास होने के बाद तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अकाली दल और कांग्रेस की सरकारें सत्ता में आने के बाद बेअदबी की घटनाओं को बढ़ावा देती थीं और धर्म-जाति के नाम पर माहौल खराब करती थीं।



चीमा ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी सरकार ने इस समस्या का स्थायी समाधान निकालते हुए सख्त कानून लागू किया है। 'सत्कार बिल 2026' को राज्यपाल की मंजूरी पंजाब में लंबे समय से उठ रही

बेअदबी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए लाया गया यह विधेयक अब कानून बनने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने 'जागत ज्योति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक-2026' को अपनी आधिकारिक मंजूरी दे दी है, जिससे इसे ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।

दोषियों के लिए उम्रकैद तक की सजा

इस संशोधन विधेयक की सबसे अहम बात इसकी सख्ती है। अब अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करता पाया जाता है, तो उसे उम्रकैद (आजीवन कारावास) की सजा दी जा सकती है। सरकार का मानना है कि इससे भविष्य में ऐसी घटनाओं पर कड़ा अंकुश लगेगा।

मुख्यमंत्री भगवंत मान का बयान

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया के जरिए इस फैसले की जानकारी साझा की। उन्होंने इसे धार्मिक भावनाओं और मर्यादा की रक्षा की दिशा में बड़ा कदम बताया और कहा कि उनकी सरकार पवित्र धर्मग्रंथों के सम्मान को बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

'क्या एक रुपया भी मिला?' AAP नेताओं पर ED की छापेमारी से भड़के अरविंद केजरीवाल

'क्या एक रुपया भी मिला?' अअड नेताओं पर ED की छापेमारी से भड़के अरविंद केजरीवाल

क्यों अहम है यह कानून?

पंजाब में बेअदबी के मामलों को लेकर लंबे समय से विवाद रहा है यह कानून धार्मिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है

सख्त सजा के प्रावधान से कानून का डर बढ़ेगा

राजनीतिक तौर पर भी यह मुद्दा पंजाब की राजनीति में बड़ा फैक्टर रहा है

सम्पादकीय

हार में जीत : हारा तो हाय, हाय जीता तो जय-जय

लोकसभा में महिला विधेयक को पारित करने के लिए दो तिहाई बहुमत की जरूरत थी किंतु सत्ता पक्ष को मात्र 298 वोट मिले जबकि विपक्ष ने एकजुट होकर 230 वोटों से इस विधेयक को पारित होने से रोक दिया। सीधे और सरल नजरिए से देखें तो यह सत्ता पक्ष की हार और विपक्ष की जीत है जबकि राजनीतिक नजरिए से देखें तो यह मामला पेचीदा हो गया है। सत्ता पक्ष महिलाओं की सहानुभूति हासिल करने के लिए इस हार को हथियार बनाने में जुटा है। जाहिर सी बात है कि विपक्ष उत्साहित और खुश हुआ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने तो सरकार पर तंज भी कसा। प्रियंका ने जो बात लोकसभा में कही वही बात उन्होंने शनिवार को लोकसभा में चर्चा के दौरान भी दोहराई कि महिलाएं मूख्य नहीं हैं। लेकिन मानना पड़ेगा कि प्रियंका को इस बात का एहसास हो गया था कि सरकार ने विपक्ष को पंसाने के लिए ही यह विधेयक पेश किया है। हारा तो हाय, हाय जीता तो जय-जय। दरअसल मोदी सरकार की लोकसभा में 2 तिहाई बहुमत नहीं है फिर भी उन्होंने संविधान संशोधन विधेयक पेश किया तो जरूर इसका कोई न कोई कारण होगा। बस, यही बात तो विपक्ष की समझ में आ नहीं रही है। सत्ता पक्ष यह संदेश देना चाहता है कि विपक्ष महिला हितों के खिलाफ है। शनिवार को अपने राष्ट्र के नाम संदेश में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इन विधेयकों के पारित होने के बाद महिलाओं को होने वाले हितों की जो जानकारी दी और यह भी कहा कि यदि महिलाएं इन हितों से वंचित होती हैं तो इसके लिए सीधे जिम्मेदार कांग्रेस, डीएमके और टीएमसी होंगी। मजे की बात तो यह है कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में हो रहे चुनावों में भाजपा का इन्हीं पार्टियों से मुकाबला है। अब भाजपा के छोटेबड़ नेता महिला विधेयक का नाम लेकर इन सभी पार्टियों पर निशाना साधेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बहस के दौरान ही इस बात का संकेत दे दिया था कि यदि यह विधेयक पारित हो जाता है तो सभी को फायदा होगा किंतु यदि नहीं पारित हुआ तो उन पार्टियों को नुकसान होना तय है। अब भाजपा और उसके साथी दलों की कोशिश यही होगी कि वह एक ही बात दोहराए कि यदि उन्हें दो तिहाई बहुमत मिला होता तो लोकसभा में यह विधेयक न गिरता। सच तो यह है कि जब संविधान संशोधन के लिए दो तिहाई बहुमत की जरूरत थी तो सत्ता पक्ष के फ्लोर मैनेजरों की समझ में यह बात क्यों नहीं आई कि यदि विधेयक गिरा तो उनका उपहास होगा। इसका यही कारण है कि सरकार इस विधेयक को पेश करके विपक्ष के राजनीति का आकलन करने में लग गई। आज का विपक्ष यह नहीं समझता कि कभीकभी उसे भी जनता में अपनी छवि को जन हितैषी साबित करने के लिए सरकार के साथ सहयोग करना भी जरूरी होता है। कई ऐसे अवसर भी आए हैं जब सत्ता और विपक्ष दोनों ने एकमत से बिल को पारित कर दिया। ऐसे मामलों में श्रेय सरकार एकतरफा नहीं ले पातीं। रही बात संविधान संशोधन की गरिमा से जोड़ना की तो यदि यह सही है तो ज्यादा से ज्यादा संविधान में संशोधन उस पार्टी ने किया जो लंबे समय से सत्ता में रह चुकी है और आज कल विपक्ष में है तो वह संविधान में संशोधन को संविधान की गरिमा का हनन बता रही है। यह एक मजाक से ज्यादा वुछ भी नहीं है। संविधान में पहला संशोधन तो 1956 में ही करके प्रेस पर आपत्तिजनक विषय वस्तु छापने पर पाबंदी लगा दी गई और 1975 में 42वें संशोधन ने तो संविधान की जान ही निकाल ली थी जिसे 1977 में फिर 42 अंशों का निरसन हुआ। वास्तविकता तो यह है कि संविधान में संशोधन जरूरत के मुताबिक होता है। बहरहाल यदि सरकार चाहे कि यह विधेयक हर हाल में पारित होना ही चाहिए तो संविधान के अनुच्छेद 108 में इस बात का प्रावधान है कि सरकार संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाए और दो तिहाई बहुमत से इस महिला संबन्धी विधेयक को पारित करके अपने संकल्प का प्रदर्शन कर सकती है। किंतु सरकार को तो इस हार को जीत में बदलना है, इसीलिए वह विपक्ष को महिला विरोधी साबित करने के लिए हर कोशिश में व्यस्त है।

लखनऊ में सजेगा 'रश्मिरथी पर्व'! रामधारी सिंह दिनकर की पुण्यतिथि पर 24-26 अप्रैल तक पर 3 दिन का भव्य आयोजन

(एजेंसी)। रामधारी सिंह दिनकर की पुण्यतिथि पर 24-26 अप्रैल तक लखनऊ में 'रश्मिरथी पर्व' आयोजित होगा, जिसमें नाटक, नृत्य नाटिका और स्मारिका लोकार्पण के साथ कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की पुण्यतिथि पर उत्तर प्रदेश सरकार तीन दिवसीय 'रश्मिरथी पर्व' का आयोजन करेगी. 24 अप्रैल को दिनकर की पुण्यतिथि से 26 अप्रैल तक इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में 'रश्मिरथी पर्व' मनाया जाएगा. इसमें तीन नाटकों एवं एक नृत्य नाटिका का मंचन होगा. लोकभवन में शनिवार को कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रेसवार्ता कर जानकारी साझा की. राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कृति रश्मिरथी के हीरक जयंती वर्ष (75 वर्ष) पर यह कार्यक्रम होगा.

पंजाब-लखनऊ मैच में पंजाब के सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्य ने मचाया गदर, लखनऊ को मिली चौथी हार

(एजेंसी)। पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 254 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया है, लखनऊ इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई। पंजाब को इस मजबूत पारी के सूत्रधार सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्य रहे, जिन्होंने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए महज 37 गेंदों पर 93 रनों की पारी खेली।

प्रियांश की इस पारी में 4 चौके और 9 गगनचुंबी छक्के शामिल थे, जिसकी बदौलत पंजाब की टीम शुरुआती झटके के बावजूद मैच पर अपनी पकड़ बनाने में सफल रही। पारी की शुरुआत पंजाब के लिए अच्छी नहीं रही थी क्योंकि प्रभासिमतन

सिंह बिना खेता खोले ही मोहम्मद शमी की गेंद पर पवेलियन लौट गए।

इसके बाद कूपर कॉनली ने प्रियांश आर्य का बखूबी साथ निभाया और 46 गेंदों में 87 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया। कोनोली ने अपनी पारी में 8 चौके और 7 छक्के जड़े, जिससे लखनऊ के गेंदबाजों पर दबाव बना रहा। कसान श्रेयस अय्यर मात्र 5 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन मध्यक्रम में मार्कस स्टोडिनिस ने 29 और शशांक सिंह ने अंत में 6 गेंदों पर 17 रनों की तेज पारी खेलकर टीम को 250 के पार पहुंचाया।

लखनऊ सुपर जायंट्स की गेंदबाजी काफी महंगी साबित हुई।

हजरतगंज से रेजीडेंसी तक, छात्रों ने जाना लखनऊ का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सफर

लखनऊ ने विश्व धरोहर दिवस पर विरासत वॉक व संगोष्ठी आयोजित कर अवध की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत उजागर की. साथ ही हजरतगंज में वॉक से छात्रों को शहर के इतिहास की

समझ मिली. (एजेंसी)।

इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज (इटैक) लखनऊ चैप्टर ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एसआई), अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज, बीकेटी स्कूल, जागुति लोरेटो स्कूल, मॉडर्न एकेडमी और खुनखुनजी गर्ल्स पीजी कॉलेज के साथ मिलकर जीवंत विश्व धरोहर दिवस कार्यक्रम आयोजित किया. इसमें विरासत वॉक (यात्रा) और शैक्षणिक संगोष्ठी के द्वारा अवध की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को उजागर किया गया. कार्यक्रम की शुरुआत

लोकसभा में क्यों अटक गया

(एजेंसी)। 17 अप्रैल 2026 की देर रात लोकसभा की कार्यवाही एक ऐतिहासिक मौके की उम्मीद लेकर शुरू हुई थी। देश की महिलाएं दशकों से जिस राजनीतिक समानता का इंतजार कर रही थीं, उसकी दिशा में एक बड़ा कदम उठने वाला था। लेकिन जब मतदान समाप्त हुआ, तो वह रात एक ओर अस्वीकृति और टालमटाल की मिसाल बनकर रह गई।

सरकार ने संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 पेश किए थे। इनका मकसद साफ था कि लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 815 करना, 2011 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का नया परिसीमन करना और 2029 से बिना किसी मौजदा सांसद की सीट छीने महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में एक तिहाई आरक्षण देना।

यह प्रस्ताव उन सभी पुरानी आपत्तियों का जवाब था जिनके कारण महिला आरक्षण विधेयक पिछले 30 साल से अटका पड़ा था। अधिक

संवाद' स्मारिका का लोकार्पण शाम 6:20 बजे से राष्ट्रीय परिसंवाद झ 'प्रकाश और प्रेरणा का पुंज: रश्मिरथी'

स्वामी विवेकानंद का योगदान शाम 7:05 बजे से 'स्वामी विवेकानंद' नाटक का मंचन इस दिन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य होंगे. साथ ही अन्य गणमान्य नेता और पदाधिकारी शामिल होंगे. 26 अप्रैल शाम 6:00 बजे राष्ट्रीय परिसंवाद झ "राष्ट्र निर्माण में लोकमान्य तिलक एवं पूर्व प्रधानमंत्री और अटल बिहारी वाजपेयी का योगदान शाम 7:05 बजे 'अटल स्वरांजलि' झ भारत रहे, कवि अटल बिहारी वाजपेयी की 10 कविताओं पर आधारित संगीतमय नृत्य नाटिका शाम 8:00 बजे 'लोकमान्य तिलक' नाटक का मंचन इस कार्यक्रम में यूपी के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे.



भागीदारों ने स्थल की वास्तुकला के वित्‍य, साहस और संघर्ष के इतिहास का अवलोकन किया, जिसने 19वीं शताब्दी के लखनऊ को आकार दिया. अवध की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत पर संगोष्ठी अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज के साथ

सकता है।' 1998 का काला अध्याय: आरजेडी सांसद सुरेंद्र प्रकाश यादव ने सदन में महिला आरक्षण विधेयक को

सकता है।' 1998 का काला अध्याय: आरजेडी सांसद सुरेंद्र प्रकाश यादव ने सदन में महिला आरक्षण विधेयक को



जबरदस्ती छीनकर फाड़ दिया। यह लोकतांत्रिक विरोध नहीं, बल्कि महिलाओं के प्रति खुली अममानना थी।

2004-2014: कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के पास पूर्ण बहुमत था।2010 में राज्यसभा ने विधेयक पास भी कर दिया और इसे 'ऐतिहासिक' बताया गया। लेकिन लोकसभा में यह विधेयक कभी पेश ही नहीं किया गया। चार साल तक बहुमत होने के बावजूद राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं दिखाई गई। उस समय

मुलामय सिंह यादव ने महिला सांसदों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की थीं, लेकिन कांग्रेस चुपठी साधे रही। कांग्रेस का विरोधाभास

महावतार परशुराम का पोस्टर आउट, खून से सना फरसा देख कांप उठेंगे अधर्मी!

(एजेंसी)। 'के.जीएफ', 'सालार' और 'कांतारा' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले होम्बले फिल्मस ने एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर तूफान लाने की तैयारी कर ली है। 'महावतार नरसिम्हा' की जबरदस्त सफलता के बाद, मेकर्स ने इस यूनिवर्स की अगली बड़ी फिल्म 'महावतार परशुराम' का 19 अप्रैल यानि आज परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर मचअवेंटेड पहला पोस्टर और टीजर जारी कर दिया है।

रिलीज हुए पोस्टर में भगवान

मार्करम ने डाला इस सीजन का सबसे महंगा ओवर, 5 जोरदार छक्कों से मचा धमाल

PBKs vs LSG: मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम में पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेले जा रहे मुकाबले में एक ऐसा ओवर देखने को मिला जिसमें मैच का पूरा रुख ही बदल दिया। लखनऊ के अनुभवी

ऑलराउंडर एडेन मार्करम के लिए यह शाम किसी बुरे सपने से कम नहीं रही, क्योंकि वे आईपीएल 2026 का अब तक का सबसे महंगा ओवर फेंकने वाले गेंदबाज बन गए हैं। पंजाब किंग्स के युवा बल्लेबाजों ने मार्करम की ऑफ-स्पिन पर ऐसा आक्रमण किया कि लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत भी अशहोय नजर आए। यह घटना पंजाब की पारी के 13वें ओवर में घटी जब क्रीज पर कूपर कोनोली और प्रियांश आर्य को जोड़ी मौजूद थी।

मार्करम की जमकर हुई धुनाई

कुलश्रेष्ठ, गोपाल सिन्हा, ललित पोखरिया और प्रफुल्ल त्रिपाठी ने पारंपरिक और आधुनिक नाट्य प्रणालियों, सहित क्षेत्रीय लोकरूपों के अपने दीर्घकालिक अनुभव साझा किए. उन्होंने अवध की नाट्य परंपराओं की ऐतिहासिक समृद्धि पर प्रकाश डालते हुए दस्तावेजीकरण, पुनरुद्धार और संस्थागत समर्थन के लिए आह्वान किया.

अवधी भाषा के संरक्षण पर जोर दूसरी विशेषज्ञ चर्चा, 'अवध की लोक परंपराएं: परंपरा और पहचान' शीर्षक से आयोजित हुईं, जिसमें पद्मश्री डॉ. विद्या बिंदु सिंह अवधी लोक साहित्य की प्रमुख विद्वान और आयोजन किया. संगोष्ठी के दो विचारोत्तेजक विशेषज्ञ चर्चाओं में पहला 'अवध का लोक रंगमंच' था, जिसमें प्रमुख रंगकर्मी सूर्य मोहन

जमीनी स्तर पर महिलाएं आगे, लेकिन संसद में पीछे

देश के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण पहले से ही मिला हुआ है। 20 से ज्यादा राज्यों की लागूमा आधी सीटें महिलाओं के पास हैं। सैकड़ों महिलाएं जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के रूप में काम कर रही हैं। वे बजट संभाल रही हैं, विकास योजनाएं चला रही हैं और साबित कर रही हैं कि महिलाएं नेतृत्व करने में पूरी तरह सक्षम हैं।

लेकिन जैसे ही बात संसद और विधानसभाओं की आती है कि जहां असली नीति-निर्माण और सत्ता होती है, विरोध शुरू हो जाता है। जमीनी स्तर पर आरक्षण स्वीकार है क्योंकि वहां सत्ता का असली केंद्र नहीं है। लेकिन संसद में एक तिहाई सीटों का बंटवारा स्थापित राजनीतिक समीकरणों को चुनौती देता है। यही कारण है कि बार-बार टालमटोल होता रहा है।

पिछले 12 सालों में महिलाओं का सामाजिक सशक्तिकरण 2014 से पहले करोड़ों महिलाओं के पास शौचालय नहीं था, स्वच्छ इंधन नहीं था, पक्का घर नहीं था और बैंक अकाउंट तक नहीं था। पिछले दशक में स्वच्छ भारत, उज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जनधन खाते और मुद्रा लोन जैसी योजनाओं ने महिलाओं के जीवन में

मौखिक परंपराओं के संरक्षण के महत्व पर जोर दिया.

मिरासिन परंपरा का विशेष प्रदर्शन कार्यक्रम का एक विशेष अंश मिरासिन समुदाय पर केंद्रित था, जो लग्‍न, जन्‍म और अन्य शुभ अवसरों पर लोक गीत गाकर परंपरा को जीवित रखने वाली महिला कलाकारों का पारंपरिक समूह है. 'मिरासिन' शब्द 'मिरास' (विरासत) से व्युत्पन्न है, जो उनकी अमूर्त विरासत के संरक्षक के रूप में भूमिका को रेखांकित करता है.

यह कार्यक्रम इटैक लखनऊ चैप्टर की संयोजक डॉ. नीतू अग्रवाल द्वारा प्रस्तावित और आयोजित किया गया, जिसमें एनकेएस चौहान, कनक रेखा चौहान, डॉ. सुमना वाघ्णीय, एके श्रीवास्तव, प्रो. निशि पांडेय और डॉ. पारुल सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा.

बड़े बदलाव लाए। यह सामाजिक सशक्तिकरण था। अब अगला चरण राजनीतिक सशक्तिकरण का होना चाहिए था – घर से संसद तक। लेकिन 17 अप्रैल को वह कदम एक बार फिर अटक गया।

इंतजार अब और लंबा नहीं चलेगा आपकी दादी ने इंतजार किया, आपकी मां ने उम्मीद लगाई और आज आपकी बेटियां अभी भी इंतजार कर रही हैं। लेकिन यह इंतजार अब सिर्फ राजनीतिक दलों की मर्जी पर नहीं टिकेगा।

भारत की महिलाएं अब किसी की अनुमति का इंतजार नहीं कर रही हैं। वे पहले से ही गांव-शहर, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय शासन के हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रही हैं। 17 अप्रैल 2026 की घटना ने साफ कर दिया कि कौन महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहता है और कौन अभी भी सत्ता साझा करने से हिचकिया रहा है।

यह विधेयक की विफलता नहीं, बल्कि एक पुरानी राजनीतिक मानसिकता की असफलता है। जब अगली बार यह मुद्दा उठेगा, तो फैसला केवल सदन की संख्या बल से नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीय महिलाओं की सामूहिक आवाज से होगा – जो अब और इंतजार करने को तैयार नहीं हैं।

सना फरसा (कुल्हाड़ी) है, जो अधर्म के विनाश की गवाही दे रहा है। फिल्म की टैगलाइन- "जहां धैर्य समाप्त होता है, वहां परशुराम का फरसा शुरू होता है!" इस टीजर ने फैंस के बीच अभी से फिल्म को लेकर उत्सुकता सातवें आसमान पर पहुंचा दी है।

होम्बले फिल्मस और कलीम प्रोडक्शन ने इस प्रोजेक्ट को 7 फिल्में की एक सीरीज के रूप में प्लान किया है। पिछला रिकॉर्ड: साल 2025 में आई 'महावतार नरसिम्हा' ने ग्लोबल लेवल पर ₹300 करोड़ का बिजनेस किया था। हालत यह थी कि लोग सिनेमाघरों के बाहर भी उतारकर भजन-कीर्तन करने लगे थे।

नई कहानी: 'महावतार परशुराम' उन अहंकारी और भ्रष्ट राजाओं के अंत की कहानी है जिन्होंने धर्म का रास्ता छोड़ दिया था। प्रोड्यूसर विजय किरागांदुर के मुताबिक, यह फिल्म आज की पीढ़ी को अपनी जड़ों और शक्ति से जोड़ने का काम करेगी।

फैंस का रिएक्शन: 'यह तो सुगामी लाफगा!' पोस्टर आते ही सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। एक यूजर ने लिखा, 'दिसंबर 2027 का इंतजार नहीं हो रहा, यह तो सुगामी लाफगा!' वहीं दूसरे ने लिखा, 'प्योर पावर, प्योर धर्म! बड़े पर्दे पर परशुराम का गुस्सा देखने के लिए हम तैयार हैं!'

क्या है रिलीज डेट? टीम में कौन-कौन? अश्विन कुमार के निर्देशन में बन रही इस फिल्म का संगीत सैम सीएस ने दिया है। फिल्म दिसंबर 2027 में बड़े पर्दे पर दस्तक देगी। विजय किरागांदुर और शिल्पा धवन द्वारा निर्मित यह फिल्म विजुअल इफेक्ट्स के मामले में 'इंडी' अडॉ जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स को टक्कर देती नजर आएगी।

